7765 करोड़ 76 लाख रु. का अनुपूरक बजट पेश

- नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए सबसे अधिक 3 हजार करोड़
- सदन में अनुपूरक बजट पर आज होगी चर्चा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 जुलाई. विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे पेश किया. अनुपूरक बजट पर बुधवार को सदन में चर्चा होगी.

7765 करोड़ 76 लाख 57 हजार 154 रुपए के अनुपूरक में सबसे अधिक राशि का प्रावधान नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए किया गया है. विभाग को सबसे अधिक 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं. अनुपूरक बजट पर बुधवार को सदन में चर्चा होगी.

दरअसल नर्मदा घाटी विकास विभाग के तहत तीन दर्जन से अधिक छोटी-बड़ी परियोजनाओं का अलग- अलग काम चल रहा है. राज्य सरकार वर्ष 2028 तक नर्मदा अथॉरिटी द्वारा आवंटित पानी का पूरा उपयोग करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है. इसलिए इन परियोजनाओं का काम तेजी से और समय पर पूरा हो सके, इसलिए ही इन कामों के लिए बड़ी राशि का इंतजाम अनुपूरक में किया गया है. इधर नर्मदा घाटी विकास के बाद सबसे अधिक राशि का प्रावधान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए किया गया है. विभाग को 2220 करोड़ 62 लाख रुपए आवंटित किए जा रहे हैं. ये राशि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही दूसरे उपक्रमों के कर्ज के साथ ही उपार्जन संस्थाओं को ऋण और ऋण अग्रिम देने पर खर्च होगी. इधर लोक निर्माण विभाग के लिए भी अनुपूरक में 1300 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जा रहा है. इसके अलावा परिवहन विभाग के लिए 101 करोड़, राजस्व और आपदा राहत के लिए 397 करोड़ 54 लाख रुपए और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के लिए भी 352 करोड़ 69 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है. गृह विभाग के लिए 157 करोड़ 34 लाख रुपए का इंतजाम किया जा रहा है.

यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन

भोपाल. विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरा. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाकर जनता की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार को 'मुर्दों की सरकार' बताते हुए आरोप लगाया कि वह आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है. इस अवसर पर उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं, युवा बेरोजगारी से परेशान हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और लगातार नए घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और महंगाई जैसे जनसरोकारों के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने के बजाय यूसीसी जैसे विषयों को प्राथमिकता देकर जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है. यदि सरकार वास्तव में जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है तो उसे किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा करानी चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि यूसीसी को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने का उद्देश्य शासन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों से बचना और जवाबदेही से ध्यान हटाना है. कांग्रेस विधायक दल ने कहा कि वह विधानसभा के भीतर और बाहर जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाता रहेगा तथा प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को प्रमुखता से सामने लाने का अपना संघर्ष जारी रखेगा.

बेरोजगारों से वसूले 297 करोड़ शिक्षा विभाग को दिये

- व्यापम की पूंजी 2021-22 में 675 करोड़ से घटकर 2024-25 में 386 करोड़ हुई
- सदन में सवाल के लिखित जवाब में दी गई जानकारी
- मामला प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का

भोपाल, 21 जुलाई. प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए व्यापम/कर्मचारी चयन मंडल द्वारा वर्ष 2022 में 137 करोड़ तथा 2023 में 160 करोड़ शिक्षा विभाग को दिये गये.

यह जानकारी मंगलवार को सदस्य प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित जवाब में सदन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी.

ग्रेवाल ने कहा कि 297 करोड रुपए लगभग एक करोड़ बेरोजगारों से वसूली गई फीस है इसमें राशि को शिक्षा विभाग को देना समझ से परे है. जबकि दो वर्ष की 2022 तथा 2023 को मिलाकर शिक्षा विभाग का बजट 59778.47 करोड़ है. व्यापम ने वर्ष 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट में 137 करोड़ को परीक्षा केंद्र पर खर्च का समन्वय तथा 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में 160 करोड़ को नगद

राशि में विलोपित बताकर हस्तांतरित किया जो की वित्तीय नियमों के विपरीत है. पूछने पर एक करोड़ बेरोजगारों से वसूले 297 करोड़ शिक्षा विभाग को देने का तथ्यात्मक कारण नहीं बताया .

> लिखित जवाब में बताया गया कि व्यापम के पास 2021-22 में फिक्स डिपॉजिट तथा नगद जमा मिलाकर 675 करोड़ थे जो 2024-25 में घटकर 386 करोड़ हो गए .2020 से जून 2026 तक 73 परीक्षाओं का आयोजन किया जिसमें से 40 भर्ती परीक्षा तथा शेष चयन तथा प्रवेश परीक्षा है . 9 भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए गए तथा 31 परीक्षा मिलाकर 51,230 का चयन किया गया . 73 परीक्षा के लिए लगभग 2 .27 करोड़ ने आवेदन किया तथा 65 परीक्षाओं में 78 .33 लाख शामिल हुए . 8 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी की संख्या नहीं बताई गई . जवाब में बताया गया कि व्यापम/कर्मचारी चयन मंडल की 2020-21 से 2024-25 तक शुल्क के रूप में 359 .50 करोड़ प्राप्त हुये . इस अवधि में आयोजित 12 से अधिक परीक्षा में फर्जीबाड़े को लेकर प्रकरण दर्ज हुए .

कौन देगा 650 करोड़ का कर्ज, यूडीए बैंक कर रहा है सर्च

- दुकान मकान बेचकर चुकाएंगे दाम
- 1124 करोड़ के खोल दिए काम
- विकास प्राधिकरण में पहुंचे एक दर्जन बैंक अफसर

प्रमोद व्यास

उज्जैन. महाकाल की नगरी में सिंहस्थ-2028 को लेकर करीब 30 हजार करोड़ रुपये के विकास और निर्माण कार्य तेज गति से चल रहे हैं. इसी कड़ी में उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) अपने हिस्से की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये का टर्म लोन लेने जा रहा है.

सोमवार को 12 से अधिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी यूडीए पहुंचे, अध्यक्ष रवि सोलंकी और सीईओ संदीप सोनी ने बैंकों को पूरी परियोजना की जानकारी दी और उनकी ऋण नीति, ब्याज दर, पुनर्भुगतान व्यवस्था तथा वित्तीय शर्तों पर विस्तार से चर्चा की. यूडीए की कुल परियोजनाओं की लागत 1124.52 करोड़ रुपये है. फिलहाल निर्माण कार्यों को गति देने के लिए लगभग 645 से 650 करोड़ रुपये के टर्म लोन की आवश्यकता है. इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी कर बैंकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं. अब इच्छुक बैंक अपनी ब्याज दर, वित्तीय शर्तें और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद सबसे कम ब्याज और बेहतर शर्तें देने वाले बैंक का चयन किया जाएगा.

यूडीए के प्रस्ताव का अध्ययन - बैठक में बैंक अधिकारियों ने भी परियोजना की वित्तीय संरचना को समझा. चूंकि ऋण राशि काफी बड़ी है, इसलिए स्थानीय शाखाओं के साथ-साथ संबंधित बैंकों के प्रधान कार्यालय भी पूरे प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे. यह भी तय किया जाएगा कि ऋण किस ब्याज दर पर मिलेगा, उसकी वापसी किस प्रकार होगी और ऋण के बदले कौन-कौन सी परिसंपत्तियां या परियोजनाएं सुरक्षा के रूप में रखी जाएंगी. **संपत्ति बेचेंगे तो भर देंगे लोन**-यूडीए अधिकारियों ने बताया कि ऋण की अदायगी विकास प्राधिकरण की व्यावसायिक योजनाओं से की जाएगी. अधिग्रहित भूमि पर जनहित की योजनाओं के तहत आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित होंगी. मकान, दुकान और अन्य संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय से बैंक का कर्ज और ब्याज चुकाया जाएगा. उद्देश्य यह है कि धन की कमी के कारण सिंहस्थ-2028 से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य की गति प्रभावित न हो.

पीएम एकता माल के पीछे भी काम

धार्मिक परियोजनाओं के साथ पीएम एकता मॉल के पिछले हिस्से के विकास पर भी 220 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इन परियोजनाओं में मंदिर परिसरों का सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं, सड़कें, पार्किंग, आधारभूत अधोसंरचना और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार शामिल है.

सोमवार से बोली चालू, 29 को खोलेंगे -यूडीए ने टर्म लोन के लिए ईओआई प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोली जमा करने की प्रक्रिया 21 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है. दस्तावेज डाउनलोड और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई शाम 5 .30 बजे निर्धारित की गई है, जबकि वित्तीय प्रस्ताव 29 जुलाई को खोले जाएंगे . इसके बाद चयनित बैंक के साथ ऋण प्रक्रिया पूरी कर विकास कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा.

कहां, कितनी राशि होगी खर्च

इस टर्म लोन से महाकाल क्षेत्र और आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थलों का व्यापक विकास किया जाएगा . इनमें कालभैरव मंदिर परिसर पर 164 .50 करोड़ रुपये, सांदीपनि आश्रम पर 160 .62 करोड़ रुपये, मंगलनाथ मंदिर पर 123 .90 करोड़ रुपये, नवग्रह मंदिर पर 120 .84 करोड़ रुपये, भूखी माता मंदिर पर 106 .57 करोड़ रुपये, बगलामुखी माता मंदिर पर 85 करोड़ रुपये, अंगारेश्वर मंदिर पर 83 करोड़ रुपये, 84 महादेव परिसर पर 30 करोड़ रुपये, गढ़कालिका माता मंदिर पर 15 .51 करोड़ रुपये तथा सिद्धवट परिसर पर 14 .58 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं .

नशीली सिरप, कार, मोबाइल एवं नगदी समेत आरोपी गिरफ्तार

सीधी, 21 जुलाई . मझौली पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 शीशी कोडीन फॉस्फेट युक्त नशीली कफ सिरप, कार, मोबाइल एवं नगदी सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है . पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी एवं एसडीओपी कुसमी संतोष तिवारी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी मझौली उनि विशाल शर्मा के नेतृत्व में मझौली पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई . पुलिस के अनुसार दिनांक 20 जुलाई को मझौली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कार क्रमांक एमपी 17 जेडआर 6323 से नशीली कफ सिरप लेकर करमाई की ओर से मझौली तरफ आ रहा है . सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम अतरैला, कूरबाबा घाटी के पास घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोका गया .

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

भोपाल, 21 जुलाई. प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. राजधानी भोपाल समेत सीहोर और रायसेन में सोमवार रात से लगातार बारिश का दौर जारी है.

बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. हालांकि, प्रदेश में अब तक हुई बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी पीछे चल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में अभी भी सामान्य से 17 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने प्रदेश के चार जिलों मुरैना, भिंड, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. इनमें भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा सहित कई जिले शामिल हैं.

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 268.1 मिलीमीटर (करीब 10.5 इंच) बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि तक सामान्य रूप से 323.2 मिलीमीटर (करीब 12.7 इंच) बारिश होनी चाहिए थी. लगातार करीब 13 दिनों तक प्रदेश में व्यापक और तेज बारिश नहीं होने के कारण वर्षा का अंतर बढ़ता गया. वर्तमान में 39 जिले ऐसे हैं जहां बारिश सामान्य से कम दर्ज की गई है.

यूसीसी के विरोध में ज्ञापन

भोपाल. मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू नहीं करने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा. भाकपा ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. पार्टी का कहना है कि यह मुद्दा समाज में अनावश्यक विवाद और असहमति को बढ़ावा दे सकता है. ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में भाकपा के राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली, एटक के प्रांतीय महासचिव कॉमरेड शिवशंकर मौर्य, भाकपा जिला भोपाल सचिव कॉमरेड अजय राऊत और कॉमरेड सियाशरण शाक्य शामिल रहे. भाकपा नेताओं ने कहा कि जनहित और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा और सभी पक्षों से संवाद के बाद ही निर्णय लेना चाहिए. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने की मांग पर विचार करने का आग्रह किया.

पृष्ठ तीन के शेष

हिरासत से रिहा राहुल, प्रियंका

इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात कर छात्रों पर हुई बर्बरता पर सदन में विशेष चर्चा कराने की लिखित मांग सौंपी थी. उसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने परीक्षा संकट और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग को लेकर भारी हंगामा किया. नारेबाज़ी और पोस्टरों के बीच सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा. विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों से जुड़े इस गंभीर विषय पर संसद में बहस से भाग रही है.

मध्यप्रदेश में यूसीसी विधेयक पारित

उन्होंने सवाल उठाया कि अभी यूसीसी जरुरी है या फिर ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण? इधर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी लगातार जारी रही, जिसके चलते अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी. बाद में सदन समवेत होने पर भी विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा. विपक्ष के इस रवैये पर सत्ता पक्ष के सदस्य भी तैश में आ गए और वे भी जमकर नारेबाजी करने लगे, इस बीच अध्यक्ष ने विधेयक पर चर्चा के लिए भाजपा के वरिष्ठ सदस्य सीतासरन शर्मा का नाम पुकारा, इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार आरएसएस का एजेंडा चला रही है. पक्ष- विपक्ष के हंगामें के चलते अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही एक बार फिर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी. सदन फिर समवेत होने पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया. इस बीच शर्मा के अलावा सत्ता पक्ष से रामेश्वर शर्मा, उमाकांत शर्मा, हरदीप सिंह डंग, ओमप्रकाश धुर्वे ने विधेयक पर अपनी बात रखी, उसके बाद सीएम ने विधेयक पर सरकार का पक्ष रखा.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60